ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-9* December-2021
Anthology : The Research

राजग काल में भारत-नेपाल राजनीतिक सम्बन्ध
India-Nepal Political Relations During Nda Period

Paper Submission: 12/12/2021, Date of Acceptance: 22/12/2021, Date of Publication: 23/12/2021

अनिता कुमारी
शोधार्थी
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश/Abstract

नेपाल और भारत ऐसे दो पड़ौसी है जिनके सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव चलता रहता है। दोनों देशों के बीच खुली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है जमीन से घिरा होने के कारण नेपाल अन्यान्य रूप से भारत पर निर्भर है। भारत के अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा हेतु तथा अपनी उदारनीति के फलस्वरूप शुरूआती दौर से ही नेपाल से अच्छे सम्बन्ध रहे है। इसी दौर को आगे बढ़ाया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने। नेपाली राजनेताओं का भारत आना और भारतीय राजनेताओं का नेपाल जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान अनेक मुद्दां पर दोनों देशों को अपनी समस्याऐं सुलझाने के लिए आवश्यक है कि वार्ताओं का दौर जारी रहे और दोनों देश एक दूसरे का हाल जानने समझने की कोशिश करें।

Nepal and India are two such neighbors whose relationship keeps on fluctuating. Nepal has an open international border between the two countries, being surrounded by land, Nepal is dependent on India. India has had good relations with Nepal since the beginning for the security of its northern border and as a result of its liberal policy. National Democratic Alliance government carried forward this round. The process of Nepalese politicians coming to India and Indian politicians going to Nepal continued. During this, it is necessary for both the countries to solve their problems on many issues that the round of talks should continue and both the countries should try to understand each other's condition.

मुख्य शब्दः शांति और मैत्री संधि, काला पानी, विश्वास निर्माण, मधेशी, माओवादी, समझौता, महाकाली नदी, आतंकवाद, व्यापार और पारगमन संधि।

Key words: Peace and Friendship Treaty, Kala Pani, Confidence Building, Madheshi, Maoist, Accord, Mahakali River, Terrorism, Trade and Transit Treaty.

प्रस्तावना

भारत व नेपाल दोनों देशों के लिए नब्बे का दशक पारस्परिक सम्बन्धों में प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से उत्साह जनक रहा। दोनों देशों के राजनेताओं ने इस बात को समय-समय पर स्वीकार किया। भारत की उदारीकरण की नीति का नेपाल को भी फायदा मिला है। भारत ने नेपाल के आर्थिक विकास के नये आयाम खोले हैं तथा नेपाल की आर्थिक आवश्यकताओं व मांगों की पूर्ति का हर संभव प्रयास किया।

वस्तुतः, भारत व नेपाल दोनों देशों के लिए पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना एक भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृति-धार्मिक आर्थिक आवश्यकता है। दोनों देशों में न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक समानता है अपितु दोनों की सीमा खुली हुई है जिसके आर-पार बेरोकटोक आया जाया जा सकता है। इससे जन-जन के मध्य सम्बन्धों की स्थापना तो हुई ही है, साथ ही सीमावर्ती प्रदेश में ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ है जो दोनों देशों में समान है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित करने वाले सामरिक कारकों का अध्ययन करना।
2. भारत-नेपाल सम्बन्धों में चीन की भूमिका का अध्ययन करना।
3. भारत-नेपाल सम्बन्धों में सुधार से सम्बन्धित सुझाव देना।
4. नेपाल में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र बहाली में स्थानीय जनमत और राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण करना।
5. भारत-नेपाल सम्बन्धों का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन करना।

दोनों देशों के मध्य इस प्रकार की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ही 1950 में शांति व मैत्री संधि की गई जो अभी तक दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के संचालन का आधार रहीं है।

नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

1 अगस्त 2000 को नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला भारत की यात्रा पर आए यह भारत यात्रा सद्भावना को बढ़ाने और अधिक विश्वास-निर्माण को ध्यान में रखकर की गई।

भारत-नेपाल सम्बन्धों और अधिक मधुर बनाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत के निम्न मुद्दे निर्धारित किये गये।

1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, कालापानी की भूमि राप्ती नदी के किनारे भारत भूमि पर लक्ष्मणपुर का बांध, नेपाल में पाकिस्तान की आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियां, भारत-नेपाल खुली सीमा को नियंत्रित करना तथा भारत द्वारा नेपाली वस्तुओं पर लगाये गये अतिरिक्त कर की समस्या आदि मुद्दों पर वार्ता हुई।

1950 की संधि पर विचार

काठमाण्डू में 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षरित भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि दोनों के सम्बन्धों को संस्थागत रूप प्रदान करती है और अपने विभिन्न प्रावधानों के कारण दोनों के बीच विशेष संबंध भी स्थापित करती है। उल्लेखनीय है कि इस संधि में किसी संशोधन का प्रावधान नहीं है और इसकी धारा 10 में सिर्फ यह कहा गया है कि कोई भी पक्ष चाहे तो एक साल की सूचना देकर इसे समाप्त करवा सकता है। परन्तु उसमें संशोधन की बात पहले से ही उठती रही है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने इस बात पर बल दिया कि इस संधि के ऐसे प्रावधानों को हटा दिया जाना चाहिए जिससे नेपाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अंग बन जाता है। परन्तु निश्चित रूप से भारत सरकार के पास कोई ऐसा ठोस सुझाव नहीं भेजा गया कि नेपाल सरकार संधि के किस अनुच्छेद में संशोधन चाहती है या इसे खत्म करना चाहती है। चाहे अनचाहे 1950 की संधि नेपाल में उभरते एक नये राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गयी । प्रधानमंत्री कोईराला और उनके विदेश मंत्री के लिए इस संधि का महत्व तो है लेकिन उन्होंने इसकी मांग दूसरे अंदाज में उठाई। यद्यपि 1950 की शांति व मैत्री संधि पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ तथा न ही किसी प्रकार की सहमति बन सकी। लेकिन संधि विवाद का मुद्दा बन गयी। नेपाल में विविध वर्गों के द्वारा इस मुद्दे का उठाया जाता रहा है।

नदी सीमा सम्बन्धी विवाद

भारत ने प्रारम्भ से ही इस मुद्दे पर उदार व लचीला रूख अपनाया। कालापानी सीमा क्षेत्र नेपाल-भारत, भारत-तिब्बत सीमा पर उपस्थित है और भारत के अधिकार में है। नेपाल दावा कर रहा है कि उसकी भूमि है और भारत को उसे खाली कर देनी चाहिए भारत का दावा है कि कालापानी प्रारंभ से भारत के पास है और ऐसा सिद्ध करने के लिए उस के पास दस्तावेज है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. पिछले दिनों से नेपाल की भूमि का प्रयोग भारत विरोधी कार्यों के लिए कर रही है। इस यात्रा के दौरान कोईराला ने आवश्वासन दिया कि अपनी भूमि का इस्तेमाल भारतीय हितों को हानि पहुँचाने के लिए नहीं होने देगा। भारत और नेपाल दोनों देशों ने ऐसे उपाय प्रस्तुत किये जिससे कि खुली सीमा का प्रयोग कोई तीसरे देश का नागरिक इन्हें हानि पहुँचाने के लिए नहीं कर सकेगा।

भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता पर विचार

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि अक्टूबर 2000 से भारत से नेपाल और नेपाल से भारत विमान की यात्रा करने वाले भारतीयों और नेपालियों का विशेष रूप से नागरिकता सिद्ध करने वाला दस्तावेज पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। परन्तु नेपाल की तराई में रहने वाले मद्धेशियों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास बतायी जाती है के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेपाल सद्भावना पार्टी इस निर्णय से अप्रसन्न है वह चाहती थी कि इस निर्णय को लागू करने से पूर्व समस्या का समाधान किया जाये।

कोईराला सरकार ने मद्धेशियों की नागरिकता से सम्बन्धित समस्या से भारत सरकार को अवगत करवाया।

नेपाली विदेशी मंत्री ने बताया कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत जाने वाले सभी प्रकार के नेपाली एक तरह से नेपाल के अनौपचारिक दूत की तरह होते हैं और उनकों भारत में आने वाली कठिनाईयों से दोनों देशों के सम्बन्ध प्रभावित होते है। अतः भारत को भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होगे।

सीमा निर्धारण सम्बन्धी वार्ता

दोनों देशों ने सीमा को वैज्ञानिक रूप से वर्णित किए जाने के लिए फील्डवर्क 2001-02 तक कर लेने का फैसला किया यह भी तय हुआ कि 2003 तक मानचित्र तैयार कर लिया जायेगा।
नेपाली प्रधानमंत्री की चार वर्ष के अंतराल में प्रथम यात्रा थी। इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में एक सकारात्मक और अर्थपूर्ण माहौल का जन्म हुआ।

नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा (6 दिवसीय 25 मार्च, 2002) ने भारत यात्रा की। अटल बिहारी वाजपेयी व देउबा के बीच लम्बी व सुखद बातचीत हुई। नेपाल और भारत ने मिलकर आतंकवाद का सफाया करने का निश्चय किया। पिछले कुछ माह से माओवादी उग्रवादी हिंसा से जूझ रहे नेपाल को भारत ने सैन्य उपकरण तथा सैन्य प्रशिक्षण सहित हर संभव सहयोग देने की पेशकश की। बल्कि भारत को नेपाल में जारी माओवादी आन्दोलनों से निपटने के लिए हर संभव मदद भी करनी चाहिए।

यह माना गया कि माओवादियों द्वारा आदर्शवाद व विचारधारा के नाम पर देश में अराजकता फैलाना न तो नेपाल के हित में न भारत के हित में। नेपाल में स्थायित्व हो। आर्थिक विकास हो वह भारत के पक्ष में है। क्योंकि अराजकता की स्थिति में नेपाल स्थित खुली सीमा से लाखों लोग प्रवेश कर सकते हैं जो भारत के लिए भी सरदर्द हो सकता है।

भारत व नेपाल पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतने घनिष्ठ संबंध है। परन्तु खुली सीमा दोनों देशों के लिए एक समस्या भी रही है। चूंकि पाकिस्तानी गतिविधियां अब पंजाब व राजस्थान के सट्टे सीमा से नहीं हो पाती। अतः वे नेपाल सीमा का उपयोग करने लगे है। यह गतिविधि भारत के लिए चुनौती के रूप में है जिसमें नेपाल का सहयोग आवश्यक है।

इस यात्रा के दौरान एक समझौता ओर हुआ जिसके अन्तर्गत भारत-नेपाल को माओवादियों से निबटने के लिए मदद करेगा। नेपाल के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण देने पर भारत राजी हो गया। इसके अलावा भारत नेपाल को हथियार भी मुहैया कराएगा इसके बदले में नेपाल ने भरोसा दिया है कि वह महाकाली नदी समझौता को लागू करेगा हालांकि दोनों पक्षों के बीच हाल ही इस व्यापार समझौते से नेपाल खुश नहीं है।

भारतीय वाणिज्य सचिव दीपक चटर्जी ने समझौते के समय नेपाल के व्यापार सचिव से कहा कि मेरे पास आधे घंटे का समय है आप समझौता कीजिए या छोड़ दीजिए आखिरकार समझौता हो गया। भारत ने इस बार नेपाल से आने वाली वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया है। यही नहीं कुछ खास वस्तुओं पर सीमा-शुल्क भी बढ़ा दिया गया। समझौते के तहत एक प्रावधान यह भी था कि नेपाल से होकर जिन वस्तुओं का भारत में आयात ज्यादा बढ़ जाएगा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत स्वतंत्र होगा।

आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों में आम राय बनी है। दोनों ही देशों में इस बात पर सहमति हुई कि सीमा पर चौकसी रखी जाए। नेपाल की शिकायत थी कि बंगाल, बिहार और आंध्रप्रदेश के माओवादी गुरिल्ला नेपाली माओवादियों को मदद पहँुचाते रहे हैं। इस बार भारत ने भरोसा दिया कि वह इसे रोकने के लिए सीमा पर विशेष इंतजाम करेगा। भारत की शिकायत थी कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सहयोग से लश्कर-ए-तोएबा व जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में गड़बड़ी फैलाने आते थे। अब सीमा पर चौसी बढ़ा कर भारत नेपाल के रास्ते आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने का निश्चय किया।

नरेश ज्ञानेन्द्र की भारत यात्रा

मार्च 2002 में नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और जून में नेपाली नरेश की भारत यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्ध निःसंदेह प्रगाढ़ हुए। दोनों देशों के मध्य अनेक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई उससे दोनों देशों के बीच संदेह के बीज समाप्त हो गए। व्यापार व पारगमन संधि का नवीकरण हुआ जो मार्च 2007 तक प्रभावी रहेगा।

नेपाली नरेश ने अपने शिष्ट मण्डल के साथ भारत यात्रा की जिसने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और नेपाल में चल रहे माओवादी विद्रोह तथा युद्ध विराम की जानकारी दी। इस समस्या के हल के लिए भारत से सहायता की अपील की जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार दोनों देशों के राजनेताओं का एक-दूसरे देश की यात्रा पर आना जाना लगा रहा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र मार्च 2003 में भारत की निजी यात्रा पर आए।

निष्कर्ष

भारत-नेपाल निकटतम पड़ौसी होने के साथ-साथ घनिष्ठ मित्र भी है। दोनों की भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विरासत की समानता दोस्ताना संबन्ध बनाये रखने को मजबूर करती है। नेपाल दुनिया के 40 भू-आवेष्टित देशों में से एक है जिसकी तीन तरफ की सीमाएं भारत से लगती है और भारत की नेपाल से 1700 किलोमीटर खुली सीमा लगती है, जिससे बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के दोनों देशों में से किसी भी देश का कोई भी नागरिक आसानी से आ जा सकता है। भारत भी अपनी किसी भी उŸारी सीमा की सुरक्षा के लिए नेपाल पर निर्भर है। अतः दोनों देश अपने-अपने हित में पूर्ति हेतु अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बी.एल.फडिया, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 2005*
2. *बी.सी.उप्रेती, भारत और नेपाल प्रगाढ़ सम्बन्धों की ओर, राजस्थान पत्रिका, फरवरी 20,2001*
3. *अर्चना उपाध्याय, भारत की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध , 2005*
4. *राजीव कुमार चौहान, भारत और नेपाल के सामरिक सम्बन्ध (1950 से अब तक), 2010*
5. *मथूरालाल शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, 2006*
6. *बी.पी. दत्त, बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, 2003*
7. *कलीम बहादुर, इंण्डियन फोरेन पॉलिसी इन ए चेंजिग वर्ल्ड, 2004*